



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, २६ अक्टूबर, १९९४/४ कार्तिक, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (A.I.) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 1994

No. 3-1/75-Karmik (NI-I).—The Governor, Himachal Pradesh, in continuation of this Department's notification of even number dated 24th September, 1994, is pleased to detain Shri B. S. Dehal, District Revenue Officer, Mandi on temporary duty to Kullu during Kullu Dussehra Festival with effect from 14th October, 1994 to 21st October, 1994 in place of Shri S. P. Rolta, HAS, Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Mandi.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above officer shall be entitled to draw TA and DA as admissible under the rules.

3. The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure 1973, is also pleased to appoint the aforesaid officer to be the Executive Magistrate with all the powers of an Executive Magistrate under the said Code, to be exercised within the local limits of Kullu Tehsil w. e. f. 14th October, 1994 to 21st October, 1994 subject to the conditions contained in the Himachal Pradesh Government Home Department letter No. Home-B (B) (12)-5/84, dated 4-12-1984 and 28-12-1994.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(एफ-शाखा)

अधिसूचनाएं

दिनांक-2, 9 जून, 1994

संख्या सार्व प्र 0 बि 0 (एफ 0) 1 (ए) 4-2/90-1.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-5-1994 के क्रम को जारी रखते हुए स्वातंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के अधीन गठित उप-समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को दिनांक/यात्रा भत्ता संलग्न अनुबन्ध के अनुसार देग होगा।

2. यह स्वर्ण मुद्रण नो. 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-200 अन्व स्कीम, 06-हिमाचल प्रदेश स्वातंत्रता सेनानी कल्याण निधि से लिया जायेगा (गैर-गोपनीय)।

3. संयुक्त बिज/उप-समिति/प्रवर सचिव (सामान्य प्रशासन) इस उप-समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को दिनांक/यात्रा भत्ता भुगतान के लिए नियन्त्रक अधिकारी होंगे। इन सदस्यों के उपरोक्त बिज भी सामान्य प्रशासन एफ-शाखा में बनाये जायेंगे।

4. इस मामले पर बिस्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संख्या 531-फिन 0 (सी 0) ए 0 (9) 1/89 दिनांक 23-5-1994 द्वारा प्राप्त कर रखी है।

अनुबन्ध

(1) यात्रा भत्ता :

(क) रेल द्वारा यात्रा :

गैर-सरकारी सदस्यों को प्रशासनिक कार्यों के लिए गैर-सरकारी यात्रा भत्ता दिया जाएगा और परसुतः प्रयोग की गई यात्रा भत्ता की जांच की जाएगी। प्रशासनिक यात्रा भत्ता का हवाला होगा।

(घ) राइक द्वारा यात्रा :

यात्रा की दशा में राइक मील दूरी, केंद्र जो रेल के साथ सम्बन्ध न हो, के बीच में, गैर-सरकारी मध्य निम्न राइक मील दूरी के हवाला होंगे :—

(i) यदि यात्रा मासिक भाड़ा लेकर की गई हो।

जैसे लोक भ्रम द्वारा एकल सीट/स्थान

(ii) मोटर गाई/स्कूटर द्वारा यात्रा की दशा में

(क) पहली श्रेण 80 पैमे प्रति कि० मी० के लिए।

(ख) समतल क्षेत्र 60 पैमे प्रति कि० मी० के लिए।

(iii) दूरी ऐसी या अपनी दूर द्वारा यात्रा की दशा में

(क) पहली श्रेण 2.50 पैमे प्रति कि० मी० के लिए

(ख) समतल क्षेत्र 2.00 रु० प्रति कि० मी० के लिए।

उपनिर्देश के अतिरिक्त उन्हें विमान से भाग्य होने वाले सवाई निवास स्थान। उनकी कुल अनुपस्थिति के लिए और सवाई निवास स्थान पर राइक नि जो सवाई के साथ सरकारी कर्मचारी को लागू नियन्त्रण और शर्तों और निम्न पैमा 5 की शर्तों के प्रकाशित दैनिक भत्ता मिलेगा।

(2) दैनिक भत्ते :

(क) गैर-सरकारी मध्य बैठक के प्रत्येक दिन के लिए जाने-मने परिक्षेत्र और प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले नियन्त्रण और शर्तों के प्रकाशित उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा।

(ख) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त मध्य घरे पर और निम्न बोर्ड/समिति के कार्य से सम्बन्ध बाहरी स्टेशन पर विराम के लिए दैनिक भत्ते का हवाला भी होगा :—

(क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो

(ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक परन्तु 12 घण्टे से अधिक न हो।

70 प्रतिशत

(ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टे से अधिक है

पूर्ण

(3)-(अ) प्रवृत्त भत्ता :

गैर-सरकारी मध्य जो उस स्थान, जहाँ बोर्ड/समिति की बैठक धारित हुई है का निवास हो, को यहाँ उपस्थित मान पर यत्रा सीमा दैनिक भत्ता जो अधिकतम 10 रुपये प्रति दिन हो लेने का हवाला नहीं होगा। इससे पहले कि दायित्व स्वीकृत किया जाये। नियंत्रक अधिकारी (Controlling officer) वाले को स्थापित होगा और ऐसा होगा जिसे आवश्यकता समझे अभिप्राय करके निवासस्थान स्थान वाले की शर्तों पर नहीं भी अपना

समाधान करेगा। यदि इस ब्यौर से उनका समाधान नहीं होता तो वह अपने बिबेक पर प्रवृत्त भले को मजबूत सीमा दूरी तक सीमित कर सकेगा। यदि ऐसा सदस्य अपनी कार वा प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मान दूरी भत्ता अनुज्ञेय दर से अधिकतम 10/- रुपये प्रति दिन के अनुसार दिया जायेगा।

(4) सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ता उसके द्वारा इस भाष का प्रमाण-पत्र पेश करने पर दिया जायेगा कि उसने उसी यात्रा के लिए सरकार के किसी अन्य स्वातंत्र्य से यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(5) गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक से सम्बन्ध की गई वास्तविक यात्रा के लिए और उसके स्थाई निवास स्थान जो पहले से ही नामित किया गया हो यात्रा भत्ते का पात्र होगा। यदि कोई सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए अपने स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान पर यात्रा करे या बैठक सम्पन्न होने के पश्चात उसके स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान या ऐसे अन्य स्थान और बैठक का स्थान जिसकी दूरी कम है को वापिस आता है।

(6) गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के खाने में प्रतिसन्धायी की दशा में हिमाचल प्रदेश खाना नियम के नियम 4.17 और 6.1 के उपबन्ध तथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) गैर-सरकारी सदस्य जो विधान सभा का सदस्य हो, में बोर्ड/समिति के काम से सम्बन्ध यात्रा का हो, समय-समय पर सहायित विधान सभा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय के खाने और भत्ते के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(8) सदस्य उनके समुन्देशन से सम्बन्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा जब विधान सभा या विधान सभा समिति जिस पर सदस्य गवर्नमेंट द्वारा है नै से विधान सभा सदस्य के नेतन और भत्ते अधिनियम के अधीन वह अपने दैनिक भत्ते ले रहे हैं, हालांकि यदि वह प्रमाणित करे कि उन्हें सदन के सत्र या विधान सभा समिति के हाजिर होने में निवारित किया गया हो और विधान सभा में कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है, वह विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(9) सदस्य जिसे विधान सभा में अनहित किया गया हो प्रवृत्त भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लेगा।

हस्ताक्षरित/-

आपुनत एवं सचिव।

(अनुराग-क)

शिमला-2, 11 अक्टूबर, 1994.

संख्या जी ए 0 डी 0 ए (बी) 8-2/93.—इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना, दिनांक 10-9-94 के पैरा 3.11 के क्रम में शिमला नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, निदेशालय, बोर्ड/निगम तथा शिक्षा संस्थाओं में दो निम्नलिखित स्थानीय प्रकाश पोषित करने का निर्णय लिया गया है:-

1. महा नवर्मा 12 अक्टूबर, 1994 बुधवार
2. भैया दूग 5 नवम्बर, 1994 शनिवार

आदेशानुसार,

आर 0 के 0 अ. नन्द,
मुख्य सचिव।

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शियाला-2, 7 सितम्बर, 1994

संख्या भाषा-सी (10)-8/92-राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, प्रार्थना बौद्ध मठ ताबो गोम्पा को वर्ष 1996 में 1000वीं वर्षगांठ मनाई जाना है जिसके मनाने एवं उचित पग उठाने हेतु उच्च स्तरीय संवाचन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) के गठन को महर्षि स्वीकृति प्रदान करते हैं। जिसमें निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए जाते हैं :

1. मुख्य मन्त्री	अध्यक्ष
2. शिक्षा मन्त्री	उपाध्यक्ष
3. प्रभागी मन्त्री पर्यटन	सदस्य
4. स्थानीय विधायक (श्री कुचींग राय)	"
5. श्री गुरुकुल लोमथान, अध्यक्ष बनास समिति, काजा	"
6. श्री भगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, ताबो	"
7. श्री जीगमद तन्जीब दोर्जे, मुख्य लामा पिन मोनिस्ट्री, स्पिन	"
8. मुख्य लामा धनचर मोनिस्ट्री, स्पिन	"
9. मुख्य लामा तंगयुत मोनिस्ट्री, काजा स्पिन	"
10. लामा जापा प्रभागी कालचकरा समेगी जिम्पा लाहोल	"
11. श्री लोचन टूल ड, प्रधान लामा महयोग धीद्व विहार, का, ३०० काजा	"
12. श्री सारखोंग टूलकु, ताबो मोनिस्ट्री	"
13. प्राचार्य संस्कृति एवं मोटी पाठशाला, केलंग	"
14. श्री शेरिंग बार्जे (मंडिन बौद्ध दर्शन) सेवानिवृत्त ए०पी० आर० आ०, केलंग	"
15. महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष उनके प्रतिनिधि	"
16. मुख्य सचिव	"
17. सचिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
18. सचिव, जनजातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
19. सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश	"
20. सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
21. सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
22. सचिव (भाषा एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
23. सचिव (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
24. सचिव (लोक सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
25. प्रबन्ध निदेशक, हि० प्र० तथा पथ परिवहन निगम हिमाचल प्रदेश	"
26. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम	"
27. जिलाधीन लाहोल, हिमाचल प्रदेश	"
28. जिलाधीन किस्तोर, हिमाचल प्रदेश	"
29. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	"
30. प्रमुख अभियन्ता, बिजली एवं जन-स्वास्थ्य	"
31. निदेशक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	"
32. निदेशक लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश	"
33. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
34. निदेशक पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
35. अतिरिक्त जिलाधीन काजा, हिमाचल प्रदेश	सदस्य-सचिव

2. उक्त समिति पूह से ताबो को जाने वाले सड़क को पक्का करने, पर्यटकों को खाने-पाने तथा ठहरने की सुविधा प्रदान करने, विभिन्न समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में इस ऐतिहासिक पर्व पर विज्ञापन दिए जाने, ठहरने के लिए सरार धर्मशाला, विश्राम गृह के निर्माण करने, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था एवं ताबो गोम्पा पर विशेष साहित्य प्रकाशित किए जाने इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेगी।

3. गैर-सरकारी सदस्य, समिति से सम्बन्धित यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने हेतु सलग्नीत अनुबन्ध के अनुसार हकदार होंगे।

4. सरकारी सदस्यों को समिति से सम्बन्धित यात्रा के लिए सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिकी भत्ता दिया जाएगा।

ANNEXURE

T.A. and D.A. to Non Official Members of the Committee.

(1) Travelling allowance:

(i) *Journey by Rail.*—They will be treated at par with Govt. servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the first grade are normally entitled, i. e. accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.

(ii) *Journey By Road.*—They will be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance at 60 paise per km. for plain areas and 80 paise per km. in hilly areas, or if journey is performed by full taxi/town car, the Member will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per km. in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km. in the hills.

(iii) In addition to the actual fare of mileage as per item (i) and (ii) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers of the State Government.

(2) Daily allowance:

(i) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

(ii) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under :

- (a) If the absence from headquarters does not exceed 6 hours.

Nil

(b) If the absence from headquarters exceed 6 hours but does not exceed 12 hours, 70%

(c) If the absence from Headquarters exceed 12 hours, Full

3. *Conveyance allowance.*—Member, resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scale indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid for, the controlling officer should verify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance at the rate admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the committee, from and to the places of their permanent residence to attend the meeting of the committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting whichever is less.

5. *Members of the parliament.*—The members of the Parliament on the Advisory Committee in respect of journey performed by him by rail, road, air and steamer, in connection with the work of Committee, shall be entitled to TA/DA on the same scale as is admissible to him under 'Salaries and Allowances of Members of Parliament' as amended from time to time.

6. *Members of Vidhan Sabha.*—The non-official members who are members of the Vidhan Sabha shall be entitled to TA/DA in respect of journeys performed in connection with the work of the Committee on the scale as the admissible to them under the Salaries and Allowances of Member of Legislative Assembly.

7. The members will not be entitled to daily allowances in connection with their assignment when the Vidhan Sabha or the Vidhan Sabha Committee on which the members are serving is in session as they will be drawing their daily allowances under the Salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly (HP) Act, 1971, from the Vidhan Sabha. However, if they certify that they were prevented from attending the session of the House or the Vidhan Sabha Committee and did not draw any daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowances at the rates as prescribed;

Provided that claims on account of travelling, halting and incidental allowances of Members for attending the meetings of Committees appointed by the Government shall be paid after these have been countersigned by the Secretary Vidhan Sabha, for encashment.

8. The provision of rules 4.17 and 6.1. of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply *mutatis* in the case of overpayment made on account of travelling allowance to non-official members.

9. The member will also not draw T.A. and D.A. including conveyance allowance which will disqualify them from the Vidhan Sabha.

10. Official Members :

The official Members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

आदेश द्वारा,

विनोद लाल,

आयुक्त एवं सचिव।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

जिमला-2, 30 सितम्बर, 1994

संख्या श्रम(ए) 4-27/93.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में अकुशल कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी 24 रुपये से 26 रुपये प्रतिदिन या 720 रुपये से 780 रुपये प्रतिमाह पुनरीक्षित कर दी जाए :--

1. कृषि।
2. सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण और भवन क्रिया।
3. पत्थर तुड़ाई या पत्थर क्रेशिंग।
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट।
5. बरत एवं काष्ठ क्रिया।
6. दुकानें तथा वाणिज्य स्थापन।
7. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद।
8. इन्जिनियरिंग उद्योग।
9. खाद्य एवं पेय।
10. झाल बुनाई और गलीचा बनाना।
11. कपड़ा एवं हीजरी उद्योग।
12. कागज उत्पाद।
13. ईंट भट्टा उद्योग।
14. लकड़ी पर आधारित तथा कर्मीचर उद्योग।
15. चाय बागान।
16. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया।
17. मध्य निर्माण शालाओं शराब कारखानों और अन्य अनुसंगिक प्रचालनों जैसे बोतल भरने।
18. सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पाद।
19. धारा मशीनें।
20. निजी औद्योगिक संस्थान।
21. कास्टिंग उद्योग।
22. चमड़ा उद्योग।
23. इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्रीज।
24. होटल/रेस्तरां।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित अनुसूचित नियोजनों के बारे में अर्ध-कुशल, कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर 8.33 प्रतिशत बढ़ा दी जाए, परन्तु यह 2 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं है।

3. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि जो कर्मकार जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों

में कृषि, सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण वानिकी तथा काष्ठ, पत्थर क्रिशिंग और पत्थर तुड़ान के अनुसूचित निवोक्तों में कार्यरत कर्मचारों की क्रमशः 25 प्रतिशत और 12/1-2 प्रतिशत की प्रस्तावित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों के अतिरिक्त और बढ़ोतरी की जायेगी। जो मजदूर सुरंगों में कार्यरत हैं, उन्हें पिछले वर्षों की तरह और 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में मजदूरी क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12/1-2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी।

4. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1947 का 5) का धारा 5 के अनुसरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिनकी उक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त प्रस्ताव पर कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे अमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को इसके राजपत्र हिमाचल प्रदेश (प्रसाधारण) में प्रकाशित होने की तारीख से दो महीनों की अवधि के अवसान से पहले विचार के लिए भेजे।

5. प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें 1-10-94 से लागू होंगी।

प्रदेश द्वारा,

एस0 एस0 सिद्धू,
वित्तियक्त एवं सचिव।

[Authoritative english text of th's Department's notification No. Shram (A)4-27/93 dated 30-9-94, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 1994

No. Shram (A)4-27/93.—Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the Minimum rates of wages of un-skilled workers should be revised from Rs. 24 to Rs. 26 per day or Rs. 720 to Rs. 780 per month in respect of the under mentioned scheduled employments :—

1. Agriculture.
2. Construction or maintenance of roads and in building operation.
3. Stone breaking or in stone crushing.
4. Public Motor Transport.
5. Forestry and Timbering operation.
6. Shops and Commercial Establishments.
7. Chemical and Chemical Products.
8. Engineering Industries.
9. Food and Drinks.
10. Shawl Weaving and Carpet Making.
11. Textile and Hosiery Industries.
12. Paper products.
13. Brick Kiln Industries.
14. Wood based and Furniture Industries.
15. Tea Plantations.
16. Manufacturing Processing as defined in section 2 (k) of Factory Act, 1948.
17. Breweries D stilleries and other incidental operation like bottling.
18. Cement Factory and manufacturing of other cement products.

19. Saw Mills.
20. Private Educational Institutions.
21. Casting Industries.
22. Leather Industries.
23. Electronic Industries.
24. Hotels/Restaurants.

2. Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the minimum rates of wages of semi-skilled, skilled and highly-skilled workers should be increased by 8.33% subject to the minimum of Rs. 2 per day in respect of the above mentioned scheduled employments.

3. Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the minimum wages of the workers working in the Tribal Areas and Backward areas engaged in the scheduled Employments of agriculture, construction and maintenance of roads, forestry and timbering, stone crushing and stone breaking should further be enhanced by 25% and 12½% respectively over and above the proposed revised minimum rates of wages. For workers working in the tunneling operation, the proposed increase in minimum wages will be further enhanced by 20% as in the past years, and in addition there will be an increase of 25% and 12½% in wages for Tribal and Backward areas respectively.

4. Now, therefore, in pursuance of section-5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish this proposal for the information of the persons likely to be affected thereby. Any objections/suggestions on the above proposal may be sent to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-1 for consideration before the expiry of 2 months from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

5. The proposed revised rates will be applicable w. e. f. 1-10-94.

By order,

S. S. SIDHU,

Financial Commissioner-cum-Secretary.

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 00 2, 6 अक्तूबर, 1994

संख्या पत्र-ए(4)2/85-1.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विकासार्थक पत्राचारिता के लिए पत्रधारों को सम्मान देने के लिये वर्ष 1993 के लिये इस विभाग की अधिसूचना संख्या पत्र-ए(4)-2/85-1, दिनांक 2-5-1994 द्वारा गठित छानबीन समिति में श्री ग्राम थानवों, स्थानीय सम्पादक, जनसत्ता, चण्डीगढ़ के स्थान पर श्री विजय मङ्गल, सम्पादक, दैनिक दिव्यत, चण्डीगढ़ को सदस्य मनोनीत करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English Text of this Government Notification Number Rev. 2E (3) 17/93, dated 26-9-1994, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th September, 1994

No. Rev. 2E (3) 17/93.—Whereas Shri Roop Singh Thakur, (Retired Judge of Himachal Pradesh High Court) has been appointed Arbitrator to give award within a period of 4 months vide notification of even number, dated 8/11-11-1993.

2. And whereas the said Arbitrator has not been able to give the award within the stipulated period.

3. Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 9 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987, is pleaded to extend the period for making the award upto 9th August, 1994.

By order,

P. T. WANGDI,

Financial Commissioner-cum-Secretary,

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 27 सितम्बर, 1994

संख्या पार० डी० डी०-1-ए(बी) (2)-2/94.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग में दिनांक 24-8-94 को हुई वैभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री टेक चन्द शर्मा, अधीक्षक ग्रेड-II, कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहर, जिला मण्डी को 2200—4000 के वेतनमान में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज निदेशालय में अधीक्षक ग्रेड-I (राजपत्रि श्रेणी-II) के पद पर स्थानापन्न (Officiating) रूप से पदोन्नत करने के सहर्ष प्रादेश देते हैं।

यह पदोन्नति श्री निरंजन राम, अधीक्षक ग्रेड-II के विरुद्ध सतर्कता विभाग में चल रहे मामले के अन्तिम निर्णय पर आधारित होगी।

इसकी परीक्षा अवधि इनके कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष होगी जिस यथा स्थिति बढ़ाया जा सकता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-2, 7 अक्तूबर, 1994

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 31/90.—क्योंकि श्री रणदीप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीशमान, विभाग खण्ड संगडाह, जिला बिरसा के निरुद्ध पुलिस थाना रेणुकाजी में दिनांक 24-6-93

को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें आरोप है कि प्राथमिक पाठशाला कोटीधमान को पुराने भवन को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से गिरा कर उसका सामान खूदे-बूदे कर दिया ;

और क्योंकि याना अध्यक्ष, पुलिस याना रैणुजजी में मामले की मांग की छानबीन की और श्री रणदीप सिंह, प्रधान का जम जेर धारा 3 (2) "ए" प्रीवेंशन ऑफ डीजे टू पब्लिक प्रोपर्टी अधिनियम, 1984 का साबित होने पर निष्कर्ष दिया गया जो बाद में बरजमानत मुक्तता पर वाशदाखत रहिा हुआ है और चालान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में प्रस्तुत किया गया है ;

और क्योंकि उपायुक्त गिरमौर से भी इस बारे रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि "प्रशासन जनता के द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पंचायत के दोरे के समय श्री रणदीप सिंह, प्रधान ने प्राथमिक पाठशाला के भवन के नव निर्माण हेतु राशि मांगी थी तथा वह पुराने भवन को गिरा कर नया भवन बनवाना चाहते थे । उन्हें राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था तथा उसे पुराने भवन को गिराने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने बारे कहा गया था ;

और क्योंकि श्री रणदीप सिंह ने श्री मित सिंह तीमर का नाम ग्राम पंचायत कोटीधमान के परिवार रजिस्टर भाग 1 से हटा दिया जिसके लिए वह सक्षम न थे ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राजपत्र, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्वीय प्राप्त है, श्री रणदीप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीधमान, ब्रह्म खण्ड संगडाह, जिला भिमाग, को अदण देते हैं कि वह अरण बाधेतिथियों न उन्हें उपरोक्त कृत्यों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 का धारा 145 के अन्तर्गत प्रधान पद से निवृत्त किया जाए । उनका उत्तर इस कारण बढाभा नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-2 इस निदेशालय में पहुच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव ।

SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd December, 1993

No. STV (Law) A (10)-3/93 — The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Project Level Environmental Management Committee in respect of Bhaba, Baner, Uhl Stage-II and Kol Dam Projects in Himachal Pradesh under the Chairmanship of the following with immediate effect :-

Sl. No. 1	Name of the Project 2	Chairman 3
1.	Bhaba Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project.
2.	Baner Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project.
3.	Uhl Stage-II Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project.
4.	Kol Dam Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project.

Official Members of each Projects

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Conservator of Forests Concerned | .. Member |
| 2. Geologist from the Department of Industries concerned | .. Member |
| 3. Superintending Engineer (IPH) of area | .. Member |
| 4. Director of Fisheries, Himachal Pradesh | .. Member |
| 5. Deputy Director (Agriculture) in the area | .. Member |
| 6. Rep. of Deputy Commissioner concerned | .. Member |
| 7. Rep. of Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh | .. Member |
| 8. Rep. of Himachal Pradesh State Pollution Control Board | .. Member |
| 9. Superintending Engineer of the Project or the seniormost SEB Engineer. | .. Member-Secretary. |

2. The functions of the committee will include exercising check on cutting of forests and compensatory afforestation, prevention of soil erosion through proper arrangement of slopes; aquatic life and tourism promotion etc.

3. These Committees may meet at short-suitable intervals at Project level Hqr. to review the progress made in implementations the safeguards by each Project authority.

4. The Official members of these committees will be entitle to TA/DA admissible under the normal rules applicable to them from their respective departments.

By order,

S. K. SOOD,
Commissioner-cum-Secretary.